



भारतीय कृषि आधारित उद्योगों का वर्तमान परिदृश्य और भविष्य की संभावनाएँ : एक समीक्षात्मक अध्ययन

Gyan Prakash

Assistant Professor, Bareilly College Bareilly, (MJPRU)

Professor Shikha

Bareilly College Bareilly, (MJPRU)

सारांश

भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि आधारित उद्योगों का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि ये न केवल किसानों की आय वृद्धि में सहायक होते हैं, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन और क्षेत्रीय संतुलित विकास को भी प्रोत्साहित करते हैं। वर्तमान समय में डेयरी, चीनी, वस्त्र, चावल मिल, खाद्य प्रसंस्करण तथा तेल उद्योग जैसे क्षेत्र कृषि पर आधारित प्रमुख उद्योगों के रूप में उभरकर सामने आए हैं। तकनीकी प्रगति, वैश्वीकरण और सरकारी नीतियों के कारण इन उद्योगों में उल्लेखनीय विकास देखा गया है, फिर भी अवसंरचना की कमी, विपणन तंत्र की जटिलता, पूंजी निवेश की सीमाएँ तथा उत्पाद गुणवत्ता में असमानता जैसी चुनौतियाँ इनके विस्तार में बाधा बन रही हैं।

भविष्य की संभावनाओं की दृष्टि से, कृषि आधारित उद्योग न केवल घरेलू बाजार को सुदृढ़ कर सकते हैं, बल्कि निर्यात की क्षमता को भी बढ़ावा दे सकते हैं। सतत विकास, मूल्य संवर्द्धन, ग्रामीण उद्यमिता, नवाचार एवं डिजिटलीकरण को अपनाकर भारत इन उद्योगों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में एक नई पहचान दिला सकता है। अतः कृषि आधारित उद्योग भारत की आर्थिक प्रगति और ग्रामीण विकास दोनों के लिए आधारशिला सिद्ध हो सकते हैं।

यह शोधपत्र भारत में कृषि आधारित उद्योगों की वर्तमान स्थिति का समीक्षात्मक विश्लेषण करता है, साथ ही उनके विकास में बाधा बनने वाले प्रमुख कारकों जैसे अपर्याप्त तकनीकी ज्ञान, विपणन कठिनाइयाँ, वित्तीय संसाधनों की कमी तथा बुनियादी ढांचे की कमजोरियों को उजागर करता है। इसके अतिरिक्त, अध्ययन इस क्षेत्र में निहित संभावनाओं की पहचान करता है, जैसे कि ग्रामीण उद्यमिता में वृद्धि, वैश्विक बाजारों तक पहुँच, जैविक उत्पादों की बढ़ती माँग और मूल्य संवर्धन के अवसर।

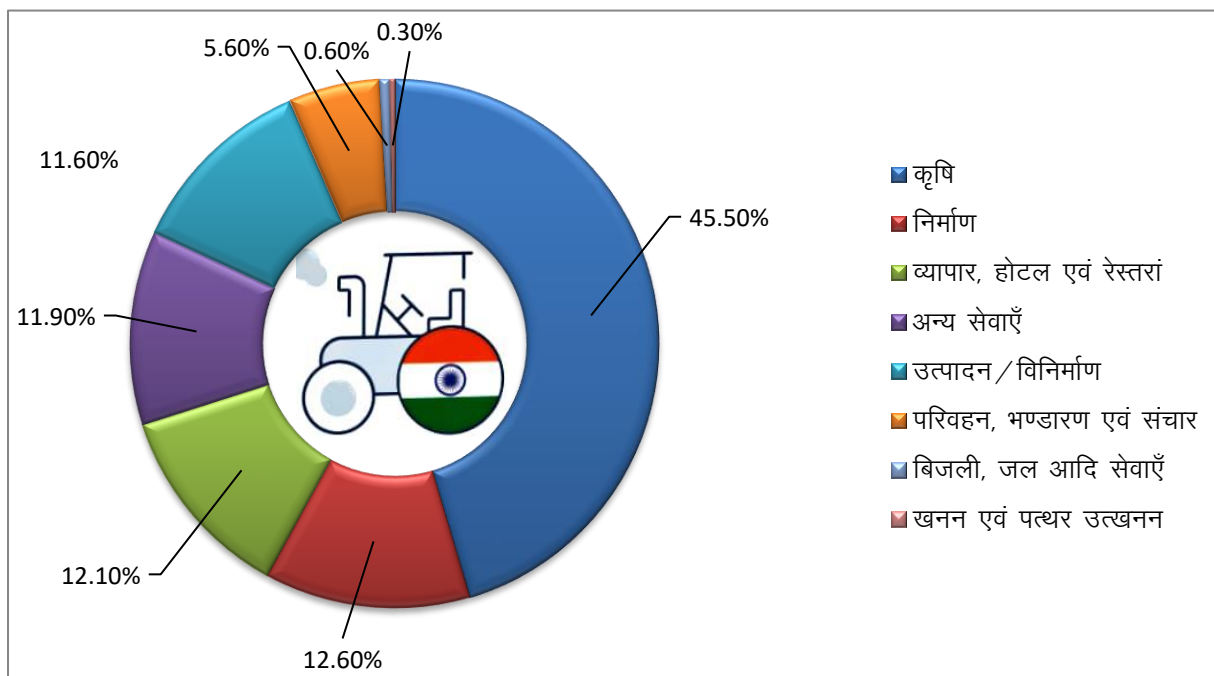
इस अध्ययन का उद्देश्य कृषि आधारित उद्योगों के महत्व को रेखांकित करते हुए, उनके सतत विकास के लिए संभावित रणनीतियों का सुझाव देना है, ताकि यह क्षेत्र आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक सशक्त कदम बन सके।

मुख्य शब्द—रोज़गार सृजन, कृषि—प्रसंस्करण उद्योग, सरकारी नीतियां, ग्रामीण रोज़गार, संतुलित विकास, तकनीकी प्रगति, डिजिटलीकरण एवं नवाचार।

प्रस्तावना (Introduction)

कृषि आधारित उद्योग वे उद्योग हैं जो कच्चे माल के रूप में कृषि उत्पादों का उपयोग करते हैं और उन्हें प्रसंस्करण कर बाजार योग्य वस्तुओं में बदलते हैं। विकास प्रक्रिया की परस्पर अग्रगामी और पश्चगामी कड़ियाँ किसी विकासशील राष्ट्र, जैसे भारत की आर्थिक प्रगति के लिए अत्यंत आवश्यक होती हैं। कृषि आधारित उद्योग, कृषि और विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों के बीच सहजीवी संबंध को अधिकतम करते हैं, जिससे अग्रगामी और पश्चगामी दोनों प्रकार के संपर्कों की वृद्धि होती है। उर्वरक, ऊर्जा, मशीनरी और कृषि पद्धतियाँ जैसे अनेक तत्व उद्योगों से प्राप्त होते हैं, जो कृषि उत्पादकता को बढ़ाने में सहायक होते हैं; दूसरी ओर, कृषि क्षेत्र उद्योगों को श्रमशक्ति और कच्चा माल प्रदान करता है।

चित्र-1 : भारत में विभिन्न उद्योगों के अनुसार श्रमिकों की भागीदारी (2021–22)



स्रोत : मिनिस्ट्री ऑफ स्टेस्टिक एण्ड प्रोग्राम इम्पीलीमेन्टेसन

भारत जैसे विकासशील देश में, जहाँ कृषि राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में 18% से अधिक का योगदान देती है और दो-तिहाई से अधिक जनसंख्या रोजगार प्रदान करती है, कृषि आधारित उद्योग अत्यधिक महत्व रखते हैं। इन उद्योगों का महत्व इसलिए भी है क्योंकि भारत की लगभग 60% आबादी कृषि पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निर्भर है। कृषि आधारित उद्योग न केवल किसानों को बेहतर मूल्य प्रदान करते हैं, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन, उद्यमिता विकास और क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने में भी सहायक हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आधारित उद्योगों को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि ये औद्योगिक और कृषि क्षेत्रों के बीच संबंधों को सुदृढ़ करते हैं

और रोजगार के अवसर उत्पन्न करते हैं। रोजगार और विनिर्माण क्षेत्र में आर्थिक योगदान का मूल्यांकन करते समय, कृषि आधारित उद्योगों का महत्व अत्यंत आवश्यक होता है—यह बात उभरते हुए और वर्तमान दोनों प्रकार के राष्ट्रों पर लागू होती है। पारंपरिक ज्ञान (ओडा) पर आधारित उद्यम एक सशक्त और समृद्ध अर्थव्यवस्था के लिए अनिवार्य होते हैं। ये क्षेत्र अब वैश्विक स्तर पर एक समान और एकीकृत आर्थिक एवं सामाजिक ढाँचे के निर्माण के लिए अति आवश्यक साधन बन चुके हैं।

उन्नत कृषि तकनीकों के कारण फसल उत्पादन में वृद्धि हुई है। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को इस लक्ष्य को प्राप्त करने का सबसे प्रभावशाली माध्यम माना जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में, जहाँ कृषि आधारित कंपनियाँ फल-फूल रही हैं, वहाँ का विकास महानगरीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक तीव्र गति से हुआ है। इन क्षेत्रों के विस्तार के लिए कृषि और उससे जुड़ी उद्योगों की प्रगति आवश्यक है, ताकि जनसामान्य की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। यह कार्य केवल संपन्नता बढ़ाने के लिए ही नहीं किया जाता, बल्कि कृषि क्षेत्र के उन मूल्यों को भी बढ़ावा देने के लिए किया जाता है, जो जीवन को सार्थक बनाते हैं।

इस शोध का उद्देश्य भारत में कृषि आधारित उद्योगों की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करना, उनकी प्रमुख चुनौतियों को पहचानना तथा भविष्य की संभावनाओं को रेखांकित करना है।

शोध के उद्देश्य

1. पिछले दशक में भारत में कृषि आधारित उद्योगों में विकास के रुझान और संरचनात्मक परिवर्तनों का विश्लेषण करना, जिसमें उत्पादन, रोजगार और निर्यात क्षमता पर जोर दिया जाएगा।
2. भारत के सकल घरेलू उत्पाद, ग्रामीण विकास और औद्योगिक उत्पादन में कृषि आधारित उद्योगों (जैसे चीनी, डेयरी, कपड़ा, चावल, आटा और कागज) के योगदान का मूल्यांकन करना।
3. कृषि आधारित उद्योगों के प्रदर्शन और प्रतिस्पर्धात्मकता को आकार देने में सरकारी नीतियों और योजनाओं (जैसे सब्सिडी, प्रोत्साहन और सुधार) की भूमिका की जांच करना।
4. कृषि आधारित उद्योगों के सामने आने वाली चुनौतियों का आकलन करना, जिसमें कच्चे माल की उपलब्धता, तकनीकी अपनाना, श्रम संबंधी मुद्दे और वैश्विक प्रतिस्पर्धा शामिल हैं।
5. भारत में विशेष रूप से कृषि आधारित उद्योगों के भविष्य की स्थिरता के अवसरों और संभावनाओं का पता लगाना।

शोध प्राविधि

इस शोध पत्र में विश्लेषणात्मक पद्धति का प्रयोग किया गया है, जिसके माध्यम से संकलित आँकड़ों का सांख्यिकीय एवं तुलनात्मक विश्लेषण किया गया है। इसका उद्देश्य भारत में कृषि आधारित उद्योगों की वर्तमान स्थिति और भविष्य की संभावनाओं को समझना तथा उनके विकास में मौजूद चुनौतियों को चिन्हित करना है।”

शोध के लिए मुख्यतः द्वितीयक आँकड़ों का उपयोग किया गया है। ये आँकड़े सरकारी रिपोर्ट, आर्थिक सर्वेक्षण, कृषि मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय, नाबार्ड तथा विभिन्न शोध पत्रिकाओं और पुस्तकों से लिए गए हैं।

आर्थिक विकास में कृषि आधारित उद्योगों का महत्व

कृषि आधारित क्षेत्रों का अर्थव्यवस्था के विस्तार पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ये देश की संपत्ति के अधिक समान वितरण के लिए उत्तरदायी होते हैं। इसके परिणामस्वरूप, आर्थिक शक्ति का अधिक न्यायसंगत रूप से आवंटन किया जा सकता है। ये सतत आर्थिक विकास के एक महत्वपूर्ण प्रेरक हैं, जो अनेक रोजगार अवसरों का सृजन करते हैं।

कृषि आधारित कंपनियों के माध्यम से विकास प्रक्रिया का विकेंद्रीकरण, समाज के सभी वर्गों के समान और समवर्ती सामाजिक-आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करता है। हमारे केंद्रीकृत योजना निर्माताओं ने इस महत्वपूर्ण तथ्य को नज़रअंदाज़ कर दिया। उन्होंने यह भूल की कि मौजूदा व्यवस्था के भीतर छोटे और अलग-थलग समुदायों की स्थापना के माध्यम से बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। अपनी पुस्तक 'एशियन ड्रामा' में गुन्नार मिर्डाल ने चेतावनी दी थी कि दक्षिण एशियाई देश, एक जड़ता से भरे वातावरण में अत्यधिक संरचित पश्चिमी शैली के उद्यमों के पृथक द्वीपों की स्थापना के जोखिम का सामना कर सकते हैं। इस स्थिति से बचने के लिए, औद्योगिकीकरण को अन्य क्षेत्रों की नीतियों द्वारा निर्देशित और समर्थित किया जाना चाहिए, ताकि समवर्ती विकास हो सके और यह केवल समकालीन बड़े पैमाने के उद्योगों तक सीमित न रहे।

कृषि आधारित उद्योगों की स्थिति का लाभ यह है कि वे अपने कच्चे माल के प्रमुख स्रोतों के निकट स्थापित होते हैं। इसके परिणामस्वरूप उत्पादन लागत घटती है और मुनाफा बढ़ता है। इस सकारात्मक प्रतिपुष्टि प्रणाली (फीडबैक मैकेनिज्म) के चलते कृषि उत्पादन में वृद्धि होती है, जिससे खेती एक लाभकारी व्यवसाय बन जाती है। कृषि आधारित उद्यम, बेहतर कृषि उपकरणों और संसाधनों की उपलब्धता बढ़ाकर कृषि उत्पादकता को बढ़ाते हैं। कृषि के स्वचालन (automation) में इन उद्योगों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन क्षेत्रों के योगदान के बिना तेज़ और टिकाऊ कृषि विकास संभव नहीं है। इसलिए, ये क्षेत्र न केवल समूची अर्थव्यवस्था, बल्कि विशेष रूप से कृषि क्षेत्र को 'टेक-ऑफ' के चरण तक पहुँचाने में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। इसके अलावा, कृषि व्यवसाय स्थानीय संसाधनों और मानवशक्ति का उपयोग कर विदेशी मुद्रा की आवश्यकता को भी कम करते हैं।

कृषि आधारित कंपनियाँ किसानों को उनकी उपज के लिए स्थायी बाज़ार प्रदान कर सुरक्षित आय सुनिश्चित करती हैं। इसके परिणामस्वरूप, देश के मानव और भौतिक संसाधनों का अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है, जो कृषि व्यवसायों के विस्तार से संभव होता है। उदाहरणस्वरूप, गन्ने के खेत में क्रशर मशीनें स्थापित करने से फसल का अधिक कुशलतापूर्वक उपयोग किया जा सकता है, जिससे परिवहन में होने वाली क्षति समाप्त हो जाएगी और परिवहन लागत भी घटेगी।

अर्थव्यवस्था के किसी एक क्षेत्र पर अत्यधिक निर्भरता किसी भी उभरती हुई अर्थव्यवस्था की समग्र प्रगति में बाधा डालती है। जो देश अत्यधिक रूप से केवल कृषि पर निर्भर रहते हैं, वे कई प्रतिकूल प्रभावों का सामना करते

हैं, जैसे कि बढ़ती बेरोज़गारी, घटती उत्पादकता, कम राजस्व, और अपर्याप्त बचत व निवेश। कृषि आधारित उद्योग ग्रामीण निर्धनता को कम करने में सहायक होते हैं क्योंकि वे कृषि क्षेत्र में निष्क्रिय श्रम शक्ति को कार्य के अवसर प्रदान करते हैं। यह कृषि आय में वृद्धि के माध्यम से प्राप्त होता है, जिससे किसान नवाचारों को अपनाने और आधुनिक तकनीक के प्रयोग के लिए प्रेरित होते हैं। इन उद्योगों का विस्तार कृषि संसाधनों और उपकरणों की उपलब्धता को बढ़ाता है, साथ ही ग्राहकों की बढ़ती मांग के अनुरूप किसानों को अपनी उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। जापान, ताइवान और डेनमार्क जैसे देशों ने यह पाया है कि कृषि आधारित उद्योग, किसानों के बीच उन्नत कृषि तकनीकों के प्रयोग को प्रोत्साहित कर कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि करते हैं।

कृषि आधारित उद्योगों को मुख्य रूप से व्यावसायिक परिवर्तन और नए सामाजिक समूहों की स्थापना के माध्यम से देखा जाना चाहिए, जो आधुनिक औद्योगिक समाज के लिए आवश्यक सामाजिक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करते हैं। कृषि आधारित उद्योग ग्रामीण क्षेत्रों को आवश्यक आर्थिक प्रोत्साहन देकर कृषि क्षेत्र को नई गति प्रदान करते हैं, साथ ही वे ग्रामीण समुदायों में बुनियादी सेवाओं के विकास में उत्प्रेरक की भूमिका निभाते हैं। तब से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच की खाई भी कम होती गई है।

कृषि आधारित उद्योगों के विकास में संलग्न एजेंसियाँ

1951 से पहले, भारत में कृषि और कृषि आधारित उद्योगों के विकास में निजी क्षेत्र का प्रमुख योगदान था, जिसमें केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों का समर्थन भी प्राप्त था। योजना काल की शुरुआत में, सरकार ने इन क्षेत्रों को उनके विकास की क्षमता प्राप्त करने में मदद करने के लिए एक अधिक सक्रिय दृष्टिकोण अपनाया। इसके अतिरिक्त, सरकार ने कृषि आधारित उद्योगों को इसके पांच वर्षीय योजनाओं में धन आवंटन के लिए एक अलग क्षेत्र के रूप में मान्यता नहीं दी है।

ग्राम और छोटे उद्योगों में कृषि आधारित उद्यमों को शामिल किया गया है, जिसमें कृषि उत्पाद प्रसंस्करण और निर्माण इकाइयाँ आती हैं, जबकि मध्यम और बड़े उद्योगों में कृषि इनपुट निर्माण इकाइयाँ या मेट्रोपोलिटन क्षेत्रों में स्थित कृषि सेवा केंद्र शामिल हैं। इन क्षेत्रों को पुनर्जीवित और आधुनिक बनाने के लिए योजनाकारों द्वारा उठाए गए मुख्य कदमों में शामिल थे :-

- (i) इन क्षेत्रों के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण बजट आवंटित करना और सहकारी समितियों का गठन करना।
- (ii) इन क्षेत्रों से संबंधित समस्याओं की जांच करने के लिए एक विशेष पैनल या आयोग की नियुक्ति करना।
- (iii) उनके विकास को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर संस्थाओं में परिवर्तित करने के लिए सुरक्षा सिद्धांतों को स्वीकार करना।
- (iv) संघीय और राज्य स्तर पर बोर्ड और संस्थाएँ स्थापित करना जो नीति निर्माण और वित्तपोषण संस्थाएँ के रूप में कार्य करें, जो इन क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा देने के लिए विकासात्मक पहलों का संचालन करें और संस्थागत और संगठनात्मक दिशा प्रदान करें।

भारत के योजनाकारों द्वारा किए गए इन पहलों के परिणामस्वरूप, केंद्रीय और राज्य स्तर पर कई सरकारी एजेंसियाँ और स्वतंत्र संस्थाएँ कृषि आधारित व्यवसायों के उन्नयन के लिए जिम्मेदार हैं।

- (i) चावल मिलें, तेल मिलें, चीनी मिलें, बेकरी, डेयरी, पोल्ट्री, कोल्ड स्टोरेज सुविधाएँ आदि कृषि मंत्रालय के तहत आती हैं।
- (ii) खादी और ग्राम उद्योग आयोग पारंपरिक कृषि आधारित उद्योगों जैसे घानी तेल, दाल, गुड़, खांडसारी प्रसंस्करण, हस्तनिर्मित कागज, और फल एवं सब्जियों का संरक्षण शामिल करता है।
- (iii) ट्रैक्टर, पावर टिलर, डीजल इंजन, और पंप सेट के निर्माण क्षेत्र वाणिज्य और विकास महानिदेशक के अधी आते हैं।
- (iv) लघु उद्यम विकास संगठन (Small Business Development Organisation) कई क्षेत्रों में लघु उद्यमों को सहायता प्रदान करता है, जिनमें होजियरी, खाद्य प्रसंस्करण, पेय पदार्थ, खाद्य और फल संरक्षण, कृषि उपकरण, कीटनाशक, उर्वरक आदि शामिल हैं।
- (v) कृषि विभाग ने संयुक्त राज्य अमेरिका में कृषि आधारित क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु एग्रोइंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन (Agro Industrial Corporation) की स्थापना की है, जो कृषि उपकरण और सेवाएँ प्रदान करने के साथ-साथ कृषि उत्पादों के उत्पादन और प्रसंस्करण का कार्य भी करता है।
- (vi) सहकारी विभाग या राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (National Co-operative Development Corporation) कपास ओटना और दबाना (cotton ginning And pressing) चीनी मिलें, स्टार्च निर्माण और चावल मिलिंग जैसे उद्योगों के विस्तार के लिए उत्तरदायी है।
- (vii) कृषि आधारित विशेष रूप से लघु उद्योगों की स्थापना की जिम्मेदारी कई राज्यों में राज्य औद्योगिक निदेशालय (State Directorate of Industry) को सौंपी गई है।

भारत का औद्योगिक विकास बैंक (Industrial Development Bank of India), कृषि पुनर्वित्त निगम (Agricultural Refinance Corporation) राष्ट्रीय सूक्ष्म उद्योग निगम (National Microscale Industries Corporation), राज्य लघु उद्योग विकास निगम (State Small Scale Industries Development Corporation) सहकारी बैंक और वाणिज्यिक बैंक कृषि आधारित उद्योगों के वित्तपोषण और उनके विकास को प्रोत्साहित करने वाली प्रमुख संस्थाओं में शामिल हैं। इस उद्देश्य के लिए औद्योगिक विकास मंत्रालय ने एक समन्वय समिति (Co-ordination Committee) का गठन किया है।

एन आईएमएसएमई (NIMSME), जिसे पहले एन आईएसआईटी (NISIT) के नाम से जाना जाता था, प्रशिक्षण, अनुसंधान, परामर्श, विस्तार सेवाएँ और सूचना सेवाएँ प्रदान कर एमएसएमई (MSME) को समर्थन

देता है। यह ज्ञान-संवर्धक विधियों के माध्यम से कार्य करता है और किसी भी संगठन के विकास की हर चरण में योगदान देता है। नीति निर्माण और योजना से लेकर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहायता प्रदान करने तक। इसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में संतुलित विकास को बढ़ावा देना है। NIMSME उद्यमियों को उनकी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रेरित करता है, उन्हें चुनौतियों से पार पाने और उपयोगी संसाधनों तक पहुँच प्राप्त करने में सहायता करता है।

NIMSME की पहलों का प्रभाव भारत से बाहर भी फैला है और यह लगभग सभी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित करता रहा है। 1967 से अब तक NIMSME ने 124 देशों के 5,900 से अधिक पेशेवरों को प्रशिक्षित किया है, और यह अपने प्रकार की पहली संस्था बनी है जिसने व्यापार विकास के कई पहलुओं में अंतरराष्ट्रीय प्रतिभागियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं। संस्थान के पाठ्यक्रम समय के साथ विकसित होते रहते हैं ताकि वे एक ऐसी दुनिया की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें जो तीव्र आर्थिक विकास की ओर अग्रसर है।

भारत में कृषि आधारित उद्योगों का प्रदर्शन

वर्ष 2020–21 तक, कृषि आधारित उद्योगों की संख्या बढ़कर 77,585 हो गई, जो 2016–17 में 56,568 थी।

यह मात्र 0.36 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर को दर्शाता है।

भारत में खाद्य-प्रसंस्करण (food processing) उद्योगों की संख्या 2018–22 के बीच उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाती है। ASI के अनुसार 2018–19 में पंजीकृत खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की संख्या 40,579 थी। दूसरे वर्ष 2019–20 में यह आंकड़ा बढ़कर 41,481 हो गया। फिर 2021–22 में यह और बढ़कर 41,913 इकाइयाँ दर्ज हुईं, और 2022–23 में यह संख्या 42,803 तक पहुँच गई। इस तरह पाँच वर्षों में पंजीकृत खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की संख्या में लगभग 5.6% की वृद्धि हुई।

भारत के कुल कृषि उत्पादन का पचास प्रतिशत से अधिक हिस्सा खाद्य और पेय उद्योग को आवंटित किया जाता है। इस उद्योग के कुल उत्पादन में अनाज मिल उत्पाद, स्टार्च और उसके व्युत्पन्न, तथा प्रसंस्कृत पशु आहार का हिस्सा 46.17 प्रतिशत है।

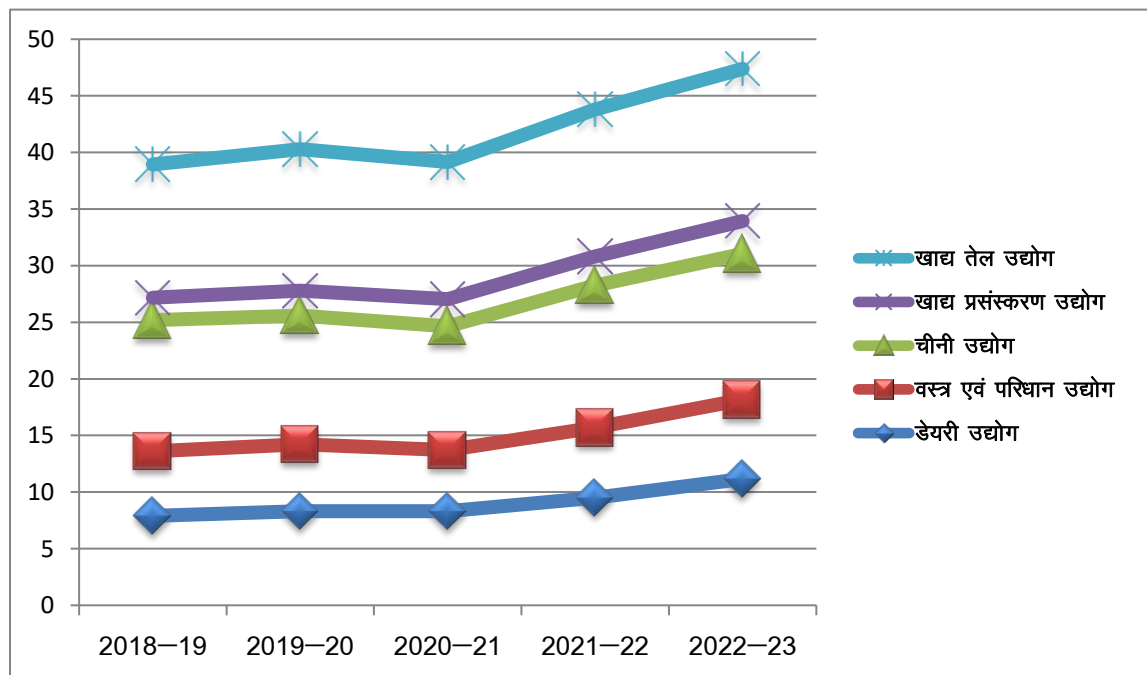
यद्यपि वस्त्र उत्पादन इकाइयाँ कुल विनिर्माण इकाइयों में सबसे अधिक हैं— खाद्य और पेय उत्पादन इकाइयों के बाद—इनकी संख्या 2016–17 से 2020–21 के बीच थोड़ी घट गई है। इस गिरावट का मुख्य कारण कताई, बुनाई और परिष्करण प्रक्रियाओं में लगातार कमी है, जिसके परिणामस्वरूप इनकी हिस्सेदारी 2016–17 में 26.57 प्रतिशत से घटकर 2020–21 में 23.96 प्रतिशत हो गई। इसी अवधि में चमड़ा उत्पाद निर्माण क्षेत्र में भी समान रुझान देखा गया है।

खाद्य और पेय क्षेत्र की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) 15.30% है। CGR का अनुमान कई वर्षों से स्थापित कंपनियों के समूहों के लिए लगाया गया है, और यह 5 प्रतिशत महत्व स्तर (significance level) पर सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण पाया गया है।

तालिका संख्या-1 : भारत के प्रमुख कृषि आधारित उद्योगों का वार्षिक उत्पादन

कृषि आधारित उद्योग	उत्पादन (लाख करोड़ रुपये में)				
	2018–19	2019–20	2020–21	2021–22	2022–23
डेयरी उद्योग	7.9	8.32	8.32	9.5	11.16
वस्त्र एवं परिधान उद्योग	5.7	5.9	5.4	6.2	7.0
चीनी उद्योग	11.58	11.38	10.92	12.53	12.88
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	2.0	2.2	2.4	2.6	2.9
खाद्य तेल उद्योग	11.76	12.48	12.12	12.96	13.44

स्रोत : सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय भारत सरकार, पशुपालन और डेयरी विभाग भारत सरकार



- डेयरी उद्योग में 2018–23 के बीच लगभग 41% की वृद्धि हुई, जो कृषि क्षेत्र में सबसे अधिक है।

- वस्त्र एवं परिधान उद्योग COVID-19 के दौरान प्रभावित हुआ, लेकिन 2022-23 में तेजी से पुनरुत्थान देखा गया।
- चीनी उद्योग ने एथेनॉल ब्लेंडिंग नीति से लाभ प्राप्त किया।
- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग ने निरंतर वृद्धि दर्ज की, जो कृषि मूल्य संवर्धन का प्रमुख स्रोत बन रहा है।
- खाद्य तेल उद्योग में घरेलू उत्पादन में वृद्धि हुई, हालांकि आयात पर निर्भरता बनी हुई है।

भारत में कृषि आधारित उद्योगों की मुख्य चुनौतियाँ

भारतीय कृषि आधारित उद्योग देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार हैं, परंतु इनके सतत विकास में अनेक संरचनात्मक, तकनीकी और नीतिगत चुनौतियाँ बनी हुई हैं। इन समस्याओं को बाहरी और आंतरिक रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। उद्यमियों को दो प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। बाहरी, जो उनके नियंत्रण से बाहर के कारकों (जैसे विद्युत आपूर्ति और आधारभूत संरचना) से उत्पन्न होती हैं; और आंतरिक, जिन्हें केवल संगठन के आंतरिक घटकों को संशोधित कर बदला नहीं जा सकता।

ये समस्याएँ कंपनी की संरचना, उत्पादन तकनीकों, वितरण चैनलों, विशेषज्ञता, प्रशिक्षण, श्रम संबंधों और प्रबंधन संबंधी कमियों से संबंधित होती हैं। नीचे उल्लिखित कुछ प्रमुख चुनौतियाँ निम्नलिखित हैं—

1. **कच्चे माल की अनियमित आपूर्ति** : कृषि उत्पादन में मौसमी अस्थिरता, जलवायु परिवर्तन और मानसूनी निर्भरता के कारण कच्चे माल की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित नहीं हो पाती, जिससे उद्योगों की उत्पादन क्षमता प्रभावित हो है।
2. **प्रसंस्करण एवं तकनीकी पिछड़ापन** : अधिकांश इकाइयाँ पारंपरिक तकनीकों पर आधारित हैं। आधुनिक मशीनरी, कोल्ड चेन और प्रोसेसिंग सुविधाओं का अभाव उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता घटाता है।
3. **वित्तीय एवं पूंजीगत कठिनाइयाँ** : ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय संसाधनों की सीमित उपलब्धता, जटिल ऋण प्रक्रियाएँ और उच्च ब्याज दरें छोटे एवं मध्यम उद्यमों के लिए प्रमुख अवरोध हैं।
4. **अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा** : ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन, भंडारण, विद्युत और संचार सुविधाओं की कमी से उत्पादन लागत बढ़ती है और मूल्य श्रृंखला कमजोर होती है।
5. **मार्केटिंग और वितरण की जटिलताएँ** : किसानों और उत्पादकों को बाजार तक पहुँच की सीमित जानकारी होती है, जिसके कारण बिचौलियों का दबदबा बना रहता है और लाभांश कम मिलता है।
6. **गुणवत्ता नियंत्रण एवं मानकीकरण की समस्या** : निर्यात योग्यता के लिए आवश्यक गुणवत्ता मानकों, पैकेजिंग और प्रमाणन की कमी से भारतीय उत्पाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते।

7. **नीतिगत असंगति और प्रशासनिक विलंब** : विभिन्न विभागों में नीतिगत समन्वय की कमी और प्रशासनिक विलंब से उद्योगों के विस्तार में बाधा आती है।
8. **पर्यावरणीय और स्थिरता संबंधी मुद्दे** : अपशिष्ट प्रबंधन, जल उपयोग और प्रदूषण नियंत्रण से जुड़ी चुनौतियाँ उद्योगों की दीर्घकालिक स्थिरता को प्रभावित करती हैं।

भारतीय कृषि आधारित उद्योगों की भविष्य की संभावनाएँ

भारतीय कृषि आधारित उद्योगों का भविष्य अत्यंत उज्ज्वल और संभावनाओं से भरा हुआ है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहाँ कृषि न केवल आजीविका का प्रमुख स्रोत है बल्कि औद्योगिक विकास का भी मजबूत आधार प्रदान करती है। आने वाले वर्षों में कृषि आधारित उद्योगों की भूमिका ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने और रोजगार सृजन में निर्णायक होगी।

सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, और उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (PLI) योजनाओं जैसी नीतियाँ कृषि प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और निर्यात को बढ़ावा देने में सहायक सिद्ध हो रही हैं। आधुनिक तकनीक जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ड्रोन तकनीक, सटीक कृषि (precision farming) और डिजिटल सप्लाय चैन का प्रयोग कृषि उद्योगों को अधिक कुशल, पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी बना रहा है। इसके अतिरिक्त, जैविक उत्पादों, प्रोसेस्ड फूड, दुग्ध उत्पादों, खाद्य तेलों और बायोप्यूल की बढ़ती वैश्विक मांग भारतीय उद्योगों के लिए निर्यात के नए द्वार खोल रही है।

ग्रामीण स्तर पर कोल्ड स्टोरेज, वेयरहाउसिंग और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के विस्तार से मूल्य श्रृंखला में किसानों की भागीदारी और आय में वृद्धि की संभावनाएँ हैं। पर्यावरणीय स्थिरता, अपशिष्ट प्रबंधन और हरित ऊर्जा के क्षेत्र में नवाचार भारतीय कृषि उद्योगों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में एक नई पहचान दिला सकते हैं। यदि नीति, वित्त और तकनीकी सहयोग का समुचित समन्वय किया जाए, तो कृषि आधारित उद्योग न केवल भारत की आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देंगे बल्कि ग्रामीण आत्मनिर्भरता, रोजगार संवर्धन और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में भी प्रमुख भूमिका निभाएँगे।

निष्कर्ष

भारतीय कृषि आधारित उद्योग देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, जो न केवल कृषि उत्पादन को मूल्य संवर्धन के माध्यम से औद्योगिक विकास से जोड़ते हैं, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन, आय वृद्धि और संतुलित क्षेत्रीय विकास को भी प्रोत्साहित करते हैं। वर्तमान परिदृश्य दर्शाता है कि यह क्षेत्र धीरे-धीरे पारंपरिक ढाँचे से आधुनिक, तकनीक-आधारित एवं बाजारोन्मुख प्रणाली की ओर अग्रसर है। सरकार द्वारा कृषि प्रसंस्करण, निर्यात संवर्धन,

कोल्ड स्टोरेज, जैविक खेती और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों (MSME) को प्रोत्साहन देने से इस क्षेत्र में नई संभावनाएँ उत्पन्न हुई हैं। हालांकि, अभी भी उत्पादन की अस्थिरता, कच्चे माल की आपूर्ति, वित्तीय संसाधनों की कमी, और गुणवत्तापूर्ण प्रसंस्करण ढाँचों की अनुपलब्धता जैसी चुनौतियाँ बनी हुई हैं। इन समस्याओं के समाधान हेतु

नीति निर्माण में दीर्घकालिक दृष्टिकोण, आधुनिक तकनीक का व्यापक उपयोग, और किसान-उद्योग सहयोग को सुदृढ़ बनाना आवश्यक है। भविष्य में यदि सरकार, निजी क्षेत्र और कृषि वैज्ञानिकों के बीच समन्वित प्रयास किए जाएँ, तो भारत के कृषि आधारित उद्योग न केवल आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को साकार करने में योगदान देंगे, बल्कि वैश्विक स्तर पर भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मकता को भी मजबूत करेंगे। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में स्थायित्व, खाद्य सुरक्षा में मजबूती, तथा पर्यावरणीय संतुलन की दिशा में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेंगे।

कृषि आधारित उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था की एक आधारशिला हैं, जो रोजगार सृजन, आय वृद्धि, औद्योगिक उत्पादन, क्षेत्रीय विकास और विभिन्न वर्गों के बीच आपसी संपर्क में योगदान करते हैं। कृषि क्षेत्र के विस्तार ने राष्ट्र के सामाजिक-आर्थिक विकास को गति प्रदान की है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि भविष्य में कृषि उत्पादों के निर्यात की अपार संभावनाएँ हैं, जो देश के लिए पर्याप्त मात्रा में विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकते हैं। जिसके लिए कृषि आधारित निर्यात के विकास के लिए लक्षित और प्रभावी उपायों की आवश्यकता होगी।

इस प्रकार, कृषि आधारित उद्योगों का विकास भारत की समग्र आर्थिक प्रगति, सामाजिक उत्थान और सतत विकास का आधार स्तंभ सिद्ध हो सकता है।

संदर्भ सूची

1. शर्मा पी. (2020) भारत में कृषि आधारित उद्योगों की वृद्धि में चुनौतियां, इंडियन जर्नल ऑफ रूरल डेवलपमेंट, पृ0सं0-45-60
2. वेंकैया वी. (2020), कृषि आधारित उद्योगों का ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर प्रभाव हिमालय पब्लिशिंग हाउस बॉम्बे, पृ0सं0-25
3. रेड्डी एम. एवं कुमार एस. (2020) भारतीय कृषि व्यवसायों के लिए विपणन और वितरण से जुड़ी चुनौतियां, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग रिव्यू, पृ0सं0-20-35
4. गुप्ता वी0 (2021), कृषि उद्योगों के लिए वित्तीय समर्थन : सरकारी पहलों का मूल्यांकन, रूरल फाइनेंस जर्नल, पृ0सं0-94-108
5. बदर ए. इक़बाल (2018) कृषि-आधारित उद्योगरू प्रदर्शन और संभावनाएँ, प्रिंटवेल पब्लिशर्स, पृ0सं0-4-10
6. बदर ए0 इक़बाल (2016) भारत में कृषि औद्योगिक विकास का वित्तपोषण, पृ0सं0-2-31
7. केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (आर्थिक सर्वेक्षण), 2019-20
8. गुन्नार मिर्डल (2019), एशियन ड्रामा, लंदन, खंड, पृ0सं0-1029
9. भारत सरकार (2018), लघु उद्योग विकास आयोग, नई दिल्ली, पृ0सं0-124-128
10. ठाकुर, एस0वाई0 (2015), भारत में ग्रामीण औद्योगिकीकरण, पृ0सं0-61-65
11. कार्ग सी0 और मिश्रा एन0 (2014), कृषि उद्योग और आर्थिक विकास, डीप एण्ड डीप पब्लिकेशन्स प्रा0 लि0 स्टर्लिंग पब्लिशर्स, नई दिल्ली, पृ0सं0-124-128
12. वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, निर्यात और आयात रिपोर्ट, 2022
13. देसाई, पी0बी0 (2019), उद्योग और कृषि के संतुलित विकास हेतु जनसंख्या परिवर्तन की प्रासंगिकता, वर्ल्ड इकोनॉमिक कांग्रेस, नई दिल्ली, खण्ड-17, पृ0सं0-14-17
14. गणेश कुमार (2011), भारतीय कृषि-प्रसंस्करण और कृषि क्षेत्रों में सुधार : एकपक्षीय और बहुपक्षीय व्यापार समझौतों के संदर्भ में, वैश्विक आर्थिक विश्लेषण पर 8वाँ वार्षिक सम्मेलन, पृ0सं0-1-34
15. विक्रमपुरी (2012), कृषि व्यवसाय : प्रतिभाशाली लोगों के लिए एक उत्कृष्ट कैरियर विकल्प, इंटरनेशनल फूड एंड एग्रीबिजनेस मैनेजमेंट, 15, पृ0सं0-27-29

16. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय भारत सरकार, पशुपालन और डेयरी विभाग, भारत सरकार रिपोर्ट, 2023
17. मिनिस्ट्री ऑफ स्टेस्टिक एण्ड प्रोग्राम इम्प्लीमेन्टेसन, 2022